

आप का सामना

हकीकत से

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, में प्रसारित

पोस्टल रजि. नंबर एचपी/33/ एसएमएल
(31 दिसंबर 2024 तक मान्य)

वर्ष- 14 अंक-24

शिमला शुक्रवार, 29 एप्रिल 2024

आरएनआई एचपीएचआईएन@2010@41180 कुल पृष्ठ-6 मूल्य- 5 ₹००

प्रोफेसर ने छात्रा से किया मोदी की कट्टर समर्थक कंगना पर रेप, होली के दिन की वारदात भाजपा का दांव मंडी से लड़ेंगी चुनाव

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शाहपुर स्थित कैंपस में पीएचडी की पढ़ाई कर रही छात्रा ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में आज यूनिवर्सिटी कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह का यह चौथा मामला है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शाहपुर कैंपस परिसर में ताला जड़ दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टीचर को किया सस्पेंड वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आरोपी प्रोफेसर राजेंद्र (44 साल) को सस्पेंड कर दिया है।

बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर शिकायत निवारण कमेटी का सदस्य भी है। आरोपी और पीड़िता ने होली वाले दिन होटल में पहले बीयर पी और साथ खाना खाया। फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी केमिस्ट्री का टीचर है पुलिस ने छात्रा के बयान पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ के खिलाफ रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरतार कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने छात्रा का मेडिकल करवाया। सूचना के अनुसार, आरोपी टीचर केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। आरोपी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई : एसपी एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पीएचडी कर रही एक छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी गिरतार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने सोमवार को होली वाले दिन छात्रा के साथ निजी होटल में रेप किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर हिमायत करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट को भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से टिकट दिया गया है। कंगना रनौट बॉलीवुड में मौजूदा पीढ़ी का ऐसा पहला बड़ा चेहरा है जो अच्छे-खासे चलते फिल्मी करियर के बीच राजनीति में कूदी है। कंगना की गिनती बॉलीवुड की मौजूदा दौर की टॉप एक्ट्रेस में होती है। लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा विरोधियों पर तीखे हमले करती रहीं कंगना अयोध्या में राम मंदिर बनाने की खुलकर वकालत कर चुकी हैं। कंगना मूलतः हिमाचल प्रदेश की ही रहने वाली हैं और उनका घर मंडी में है। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। भाजपा ने उन पर दांव लगाकर इस पहाड़ी राज्य की सियायत में पहली बार ग्लैमर का तड़का लगाया है। प्रदेश में बॉलीवुड का कोई स्टार पहली बार चुनाव लड़ेगा।

पर माइक्रो वर्किंग कर रहे हैं। हिमाचल की बाकी 3 सीटों के मुक. अबले मंडी में कड़े मुकाबले के आसार देखकर भाजपा ने यहां से कंगना को उतारने का फैसला लिया। यहां सेलिब्रिटी कार्ड के साथ-साथ कंगना के लोकल कनेक्शन को भुनाने की रणनीति है। करण जौहर को बता चुकी मूवी माफिया कंगना रनौट फिल्मों के साथ-साथ कई सेलिब्रिटीज के साथ पंगे की वजह से चर्चा में रही हैं। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलने वाले नेपोटिज्म यानी भाई-भतीजावाद के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। नेपो किड्स उनके निशाने पर रहे हैं और वह आउटसाइडर्स के लिए आवाज उठाती रही हैं। कंगना ने एक बार बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और धर्मा प्रोडक्शन कंपनी के कर्ता-धर्ता करण जौहर के शो कॉपी विद करण में उनको मूवी माफिया और नेपोटिज्म का लैग बियर तक बता दिया था। कंगना ने कहा था कि करण जौहर केवल स्टार किड्स को प्रमोट करते हैं और छोटे शहरों से आने वाले कलाकारों को बॉलीवुड में टिकने नहीं देते। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद भी कंगना ने बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ बयान दिए। नेपोटिज्म पर उनके बयान के बाद करण जौहर के साथ-साथ सलमान खान, आलिया भट्ट जैसे सितारे भी सवालियों के घेरे में आ गए। महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार के दौरान मुंबई में कंगना रनौट का दफतर तोड़ने के बाद भी वह खूब चर्चा में रही थीं। कंगना रनौट को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवॉर्ड मिल चुका है। 8 नवंबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ को. विंद ने उन्हें यह सम्मान दिया था। कंगना भाजपा के विरोधी दलों और उनकी ओर से चलाए जाने वाले आंदोलनों पर तलख टिप्पणियां करती

रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने धरना देने वाली महिलाओं के बारे में कह दिया था कि ये लोग 100-100 रुपए लेकर धरने में आती हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ पंजाब के कोर्ट में मानहानि का केस भी किया गया। राजपूत परिवार में जन्मी कंगना को शुरू से मॉडलिंग का शौक रहा। इसके चलते वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। कंगना के माता-पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने 10वीं के बाद उन्हें पढ़ने के लिए चंडीगढ़ भेज दिया। कंगना ने 12वीं तक की पढ़ाई चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से की। कंगना की डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी इसलिए वह 16 साल की उम्र में मुंबई चली गईं। मुंबई जाने से पहले उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ में मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली। पहली ही फिल्म छोड़ दी, गैंगस्टर से किया डेब्यू कंगना रनौट 17 साल की उम्र में वर्ष 2004 में मशहूर डायरेक्टर पहलाज निहलानी के निर्देशन में बन रही फिल्म से डेब्यू करने वाली थीं। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद कंगना ने किसी वजह से फिल्म बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। अपनी पहली ही फिल्म से कंगना को बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। इसके बाद उन्होंने वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, वन्स अपोन अ टाइम इन मुंबई, तनू वेड्स मनु . ष, क्वीन, और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। आखिरी फिल्म तेजस रही लॉफ, इंदिरा पर बनी इमरजेंसी से चर्चा में कंगना की आखिरी रिलीज फिल्म तेजस थी लेकिन वह लॉफ रही। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म खुद कंगना ने ही डायरेक्ट की है। पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में कंगना ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है।

चुनाव रणनीति बनाई शिक्षा मंत्री ने शिमला सोलन और सिरमौर के जिला अध्यक्षों के साथ

शिक्षा मंत्री और शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी रोहित ठाकुर ने शिमला, सोलन और सिरमौर के पार्टी जिला अध्यक्षों को बूथ स्तर तक सीधा संपर्क बनाए रखने और आपसी तालमेल में कोई कमी नहीं रखने का आह्वान किया है। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में उन्होंने चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रति भाजपा सांसद की उदासीनता को चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने पार्टी जिलाध्यक्षों व अग्रणी संगठनों से लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान करते हुए कहा है कि शिमला सीट पर इस बार हर हाल में जीत हासिल करनी है। इस क्षेत्र के भाजपा सांसद अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता से बहुत दूर रहे। लोग उनकी शकल तक भूल गए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि जिला अध्यक्षों को सभी ब्लॉक अध्यक्षों के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य करना होगा। उन्हें सभी ब्लॉकों के दौरे कर बूथ व वीएलओ के साथ सीधा संपर्क रखना होगा। इसी प्रकार अग्रणी संगठनों के सभी प्रमुखों व पदाधिकारियों को भी पूरे तालमेल से कार्य करना होगा। सरकार के एक साल की उपलब्धियां व कर्मचारियों को ओपीएस के साथ महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी को सरकार ने पूरा किया है। इन्हीं बातों को लेकर पार्टी को जनता के बीच जाना होगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाले लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव हम सबकी एक परीक्षा है, जिसमें हमें हर हाल में सफल होना है। विधानसभा के उपचुनाव भाजपा की देन है। सत्ता की लालसा के चलते भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की है। भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

मंडी लोकसभा सीट पर कंगना के सामने कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी? यह फिलहाल तय नहीं है। 2021 में भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां से सांसद बनीं लेकिन हाल ही में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मंडी लोकसभा सीट पर वर्ष 2009 से 2024 के बीच हुए 2 उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ही यहां से विजयी रहीं। सेलिब्रिटी के साथ-साथ लोकल भी कंगना रनौट मूल रूप से हिमाचल में मंडी जिले के भांबला गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने मनाली में अपना घर भी बना रखा है जो मंडी संसदीय हलके में ही पड़ता है। दरअसल मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी जिले की 10 में से 9 विधानसभा सीटों के अलावा कुल्लू जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। इस बार लोकसभा की 370 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मैदान में उतरी भाजपा के रणनीतिकार हर सीट

बागियों की हार निश्चित, जनता देगी जवाब : कांग्रेस

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह एवं मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि विश्वासघात करने वाले नेताओं को जनता विधानसभा उपचुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा बागियों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है और धनबल से जनादेश को प्रभावित कर सत्ता पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा गया। प्रदेश की जनता के सामने उनका असली चेहरा आ चुका

है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे नेता कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को नीलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए बागियों की हार निश्चित है। दोनों नेताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सत्ता लोभ जा नहीं जा रहा है और वह सत्ता हथियाने के लिए गुलत हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हीं के लालच ने प्रदेश को अस्थिर करने का प्रयास किया। भाजपा दोफाड़ होने को है और पार्टी अपना कुनबा संभाल नहीं

पा रही है। भाजपा के कई विधायक, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकते हैं। भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी से नाराज होकर अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जयराम ठाकुर सिर्फ मुख्यमंत्री के लालच में फँसे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागियों को टिकट मिलने से भाजपा की साजिश हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है।

ई साप्ताहिक अखबार
‘आप का सामना’
इंटरनेट पर भी पढ़िए।
www.aapkasaamna.com

लॉग ऑन करें
www.aapkasaamna.com

आपका सामना

34&34 होगी जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती, उस दिन भाजपा की सरकार होगी : जयराम

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा जिस दिन प्रदेश में विधायकों की गिनती 34-34 होगी। उस दिन प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी। बागी विधायकों पर जयराम ने कहा कि उन्होंने भाजपा के प्रति समर्थन जताया था। उनको टिकट देकर पार्टी ने नैतिकता निभाई है। कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। सुख की सरकार की विदाई की शहनाई बज चुकी है। इसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। सरकार बनने के बाद विधायकों को भी सीएम मिलने का समय नहीं देते थे।

अब वक्त ऐसा आया कि विधायकों को चाय पीने के लिए बुलावे आ रहे हैं और विधायक जाना नहीं चाहते हैं। कहा कि सुख देने का दावा करने वाली सरकार ने किसी वर्ग को सुख नहीं दिया। सरकार के मंत्री पिता की प्रतिमा लगाने के रोते हुए त्यागपत्र देते हैं और डिप्टी सीएम उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। सरकार के पास बजट पास करने के लिए भी बहुमत नहीं था। इसके लिए पहले भाजपा के

15 सदस्यों को निलंबित किया और उसके बाद बजट पास किया। केएल बोले-लंबी छुट्टी के बाद घर वापसी, मंडल अध्यक्ष ने बनाई दूरी भाजपा में शामिल होने के बाद नालागढ़ पहुंचे विधायक केएल ठाकुर के स्वागत में खेड़ा गांव से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप व शिमला संसदीय सीट के प्रभारी सुखराम चौधरी के नेतृत्व में रोड शो निकाला गया। सोबन माजरा में जनसभा में उपस्थित लोगों को पहले आजाद और भाजपा में शामिल होने के सफर के बारे में केएल ठाकुर ने विस्तार से जानकारी दी। हालांकि, भाजपा के इस स्वागत कार्यक्रम से नालागढ़ भाजपा मंडल ने दूरी बनाए रखी। पूर्व विधायक लखविंद्र सिंह राणा, मंडल अध्यक्ष मनोहर लाल ठाकुर समेत मंडल का कोई भी पदाधिकारी समारोह में नहीं पहुंचा। केएल ठाकुर ने कहा कि वह भाजपा के थे और भाजपा के ही रहेंगे। वह किसी कारण लंबी छुट्टी गए हुए थे और छुट्टी समाप्त होने पर वापस भाजपा में आ गए। लेकिन वह कांग्रेस

की जय कभी नहीं कहेंगे। उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव यहां की जनता के कहने पर लड़ा था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने से यहां पर विकास करवाने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया था लेकिन कांग्रेस में कोई काम नहीं हुआ तो उन्होंने घर वापसी करना ही ठीक समझा।

नौकरी छोड़ उन्होंने ने इसी स्थान पर भाजपा को 2012 में ज्वाइन किया था और अब दोबारा इसी जगह दोबारा भाजपा में शामिल हुए।

जब मंत्री व विधायक के नहीं हुए काम, तो जनता का क्या हाल रुकश्यप सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, जब पंद्रह माह के भीतर सरकार के विधायक व मंत्री विरोध करने लगे हैं। इनकी ही पार्टी के विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं कि उनके विस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। जब विधायकों के काम नहीं हुए तो आम जनता के काम कहाँ होंगे।

भाजपा कैंडिडेट कंगना रनोट पर 8 केस 3 मानहानि के मामले

हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं बॉलीवुड की गर्ल नाम से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनोट पर आठ केस चल रहे हैं। इनमें ज्यादातर केस महाराष्ट्र की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। यह जानकारी हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत यह जानकारी -7 फॉर्म में चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को शेयर करनी होती है। दो अखबारों में भी इसका विज्ञापन प्रकाशित करना होता है। भाजपा ने कंगना के -7 फॉर्म में बताया कि कंगना के बराबर के कैलिबर को कोई नहीं था। इसलिए उन्हें मंडी से प्रत्याशी बनाया गया है। कैंडिडेट बनाने के बाद कंगना रनोट ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

अब कंगना पर दर्ज केसों के बारे में पढ़िए... मुंबई में जावेद अख्तर ने कर रखा मानहानि का केस -7 फॉर्म पर शेयर जानकारी के अनुसार, कंगना रनोट पर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने मानहानि का केस कर रखा है। यह केस मुंबई के अंधेरी कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें चार्जज फ्रेम हो गए हैं। मगर कंगना ने अदालत में काउंटर एप्लिकेशन दायर कर इस केस पर रोक लगाने की मांग कर रखी है। दरअसल, 2020 में जब जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का मुकदमा किया था, तब पलटवार करते हुए

कंगना ने भी उन पर मानहानि का केस किया। बीते साल जावेद अख्तर को मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन कंगना पर लगाया गया जावेद का मुकदमा अब भी जारी है।

क्या था पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनोट ने बॉलीवुड के कई लोगों पर संगीन आरोप लगाए थे। कंगना ने इसी दौरान ऋतिक रोशन और उनसे जुड़े लोगों पर भी विवादित बयान दिए थे। कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी कि अगर उन्होंने ऋतिक को परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कंगना का यह बयान सामने आने के बाद जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

कंगना और आशीष के बीच की लड़ाई दूसरा केस कंगना बनाम लेखक आशीष कौल के बीच बांद्रा कोर्ट में चल रहा है। आशीष कौल ने कंगना के खिलाफ कॉपी राइट के उल्लंघन का मामला दर्ज करा रखा है। इस मामले में भी कंगना ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। कंगना ने कुछ साल पहले अनाउंसमेंट की थी कि वह जल्द मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा नाम की फिल्म बनाएंगी। यह फिल्म जिस किताब पर आधारित है उसके लेखक आशीष कौल है। कंगना के अनाउंसमेंट के बाद ही आशीष ने कंगना के खिलाफ कॉपी राइट उल्लंघन का केस किया है।

पंजाब की महिला किसान शाहीन बाग की दादी बताने पर विवाद पंजाब की महिला किसान महिंदर कौर ने भी कंगना रनोट के खिलाफ बठिंडा

की अदालत में केस कर रखा है। कंगना ने टिवटर पर महिंदर कौर को शाहीन बाग की दादी बताया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, कंगना की टिप्पणी से उनकी प्रतिष्ठा कम हुई और उन्हें मानसिक तनाव, पीड़ा, उत्पीड़न, अपमान सहन करना पड़ा। महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है। आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी ने भी कर रखा केस

आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब और कंगना के बीच भी अंधेरी कोर्ट में केस चल रहा है। इसी तरह एक अन्य मामला आदित्य पंचोली ने भी कंगना पर दर्ज करा रखा है। एक वक्त था जब आदित्य पंचोली और कंगना रनोट का अफेयर काफी सुर्खियों में था। मगर कुछ समय बाद दोनों में अनबन हो गई।

ब्रेकअप के बाद दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। कंगना ने अपने पुराने कई इंटरव्यू में आदित्य पंचोली पर शारीरिक हिंसा और मारपीट करने का आरोप लगाया था।

इसके बाद आदित्य पंचोली ने कंगना रनोट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यह केस अंधेरी कोर्ट में चल रहा है।

कर्नाटक में शांति भंग करने का केस कंगना के खिलाफ एक अन्य मामला कर्नाटक के तुमकुर जिले की अदालत में चल रहा है। दरअसल, कंगना ने अपने एक ट्वीट के जरिए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर निशाना साधा था।

रमेश नायक ने कंगना पर धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने व शांति भंग करने का मामला दर्ज करा रखा है।

पुरानी पेंशन भाजपा शासन वाले किसी राज्य में नहीं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ वायदे ही नहीं करती है, उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने के बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा के शासन वाले

किसी भी राज्य में पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। जहां दी जा रही थी, वहां पर भी बंद कर दी गई है। जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में 1.36 लाख

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ दे रही है। कर्मचारियों की भलाई के मामले में प्रदेश सबसे आगे होगा। हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस की बहाली कांग्रेस के शासनकाल में की गई है।

ब्राह्मण कार्ड खेला भाजपा ने राजीव भारद्वाज को टिकट देकर, कांगड़ा में 23 प्रतिशत वोट पर नजर

भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा सीट से डॉ. राजीव भारद्वाज को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। शांता कुमार के राजनीति से सन्यास लेने के बाद कांगड़ा में भाजपा को ब्राह्मण नेता की तलाश में थी। पार्टी ने यहां से सीटिंग एमपी किशन कपूर का टिकट काटकर राजीव भारद्वाज पर भरोसा जताया है।

राजीव भारद्वाज, शांता कुमार के भी करीबी रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश भाजपा नेताओं से भी अच्छे संबंध रहे हैं। डॉ. भारद्वाज बचपन से ही स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री ली है।

राजीव भारद्वाज ने 1989 में भारतीय जनता पार्टी जॉइन की। तीसरी बार वह भाजपा के उपाध्यक्ष बने हैं। भाजपा की सरकारों में वह कई बार विभिन्न पदों पर तैनात रहे। प्रेम कुमार धूमल की सरकार में 2008 से 12 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम में उपाध्यक्ष रहे, जबकि पूर्व जयराम सरकार में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन बने।

राजीव भारद्वाज को इसलिए दिया गया टिकट

राजीव भारद्वाज को टिकट मिलने की दो बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली हिमाचल में सियासी उठापटक और दूसरा जातीय समीकरण। हिमाचल सरकार पर संकट से पहले कांगड़ा सीट से विपिन सिंह परमार को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चाएं थी। अब 9 विधायकों के भाजपा जॉइन करने के बाद विधानसभा में कभी भी संख्याबल की नौबत आ सकती है। इसलिए भाजपा ने सीटिंग एमएलए को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला लिया है।

23 प्रतिशत ब्राह्मण आबादी साधने को फैसला

वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की एक भी सीट पर ब्राह्मण नेता नहीं उतारा था। तब भाजपा ने 11 सीटों पर राजपूत और अन्य 6 सीटों पर दूसरी कम्युनिटी से कैंडिडेट दिए थे। तब भाजपा 17 में 11 सीटों पर चुनाव हार गई थी। भाजपा नेता संजय भारद्वाज के अनुसार, प्रदेश में 23 फीसदी ब्राह्मण आबादी है। इसलिए भी भाजपा ने राजीव भारद्वाज पर दांव खेला है। कांगड़ा के दो दिग्गज ब्राह्मण नेता

बाहर कांगड़ा हल्के से शांता कुमार और राजन सुशांत भाजपा में दो बड़े ब्राह्मण नेता रहे हैं। शांता राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, जबकि राजन सुशांत भाजपा से बागी हो गए हैं। ऐसे में भाजपा को नए ब्राह्मण नेता की तलाश थी। चर्चा यह भी थी कि हाल में भाजपा में शामिल धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को भी ब्राह्मण नेता के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सुधीर को आम चुनाव में न लड़ाने का निर्णय लिया और 58 साल से राजीव भारद्वाज को टिकट दिया।

कांग्रेस ने 2009 में विरोध के बाद वापस ले लिया था मदनलाल का टिकट

इससे पहले 2009 में कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर और 1983 की वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे मदनलाल शर्मा को हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया था लेकिन, जनता के विरोध के बाद उनका टिकट वापस लेना पड़ गया। मदनलाल शर्मा का जन्म पंजाब में अमृतसर के एक गांव में हुआ था। उनका परिवार हिमाचल प्रदेश के धनौटा गांव से ही पंजाब गया था।

एचपीयू में 308 करोड़ का बजट किया पारित, 100 करोड़ से बनेंगे नए भवन

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) को लागू करने की तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। प्रदेश सरकार से हरी झंडी मिलने पर ही एनईपी को लागू किया जाना है। विवि कुलपति ने नीति को कॉलेजों में 2024 से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर सोमवार को विवि के कार्यवाहक कुलपति प्रो. एसपी बंसल की अध्यक्षता में विवि के सभी अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों और विवि के अधिकारियों ने भाग लिया। विवि को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से मिली 100 करोड़ की ग्रांट को विश्वविद्यालय विकास के लिए खर्च करने के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में कुलपति ने कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी के लिए अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बीके शिवराम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने और पूर्व डीएस प्रो. कुलभूषण चंदेल को इसका समन्वयक बनाने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और मेरु को धरातल पर उतारने के लिए तैयारी करेगी, जिससे विवि से संबद्ध कॉलेजों में नीति को लागू किया जा

सके। कुलपति ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मिले सौ करोड़ को चार मुख्य भागों में बांट कर विवि के विकास कार्य में बांटकर खर्च किया जाएगा। इसमें नए भवन के निर्माण, भवनों के जीर्णोद्धार, तीसरे प्रयोगशालाओं को अपडेट करने, उपकरण खरीदने शोध में गुणवत्ता सुधार लाने के अलावा सॉफ्ट कंपोनेंट में वेबसाइट का सुदृढीकरण करने जैसे कार्य पर खर्च किया जाएगा। कुलपति ने कहा कि इस राशि को दो सालों में खर्च किया जाएगा। हर कैंपस को हमें मेरु के तहत परिवर्तित लाए जाएंगे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के सुदृढीकरण करने के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश कुलपति ने दिए। उन्होंने पीएम उषा में हर विभाग को मासिक और त्रैमासिक न्यूज लैटर की रिपोर्ट जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। कुलपति ने कहा कि नए सत्र में हर विद्यार्थी को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है। यह एक सरकारी पोर्टल है, उसमें पंजीकृत होना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रति-कुलपति आचार्य राजिंद्र वर्मा, पूर्व प्रति-कुलपति आचार्य ज्योति प्रकाश, अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बाल कृष्ण के अतिरिक्त सभी अधिष्ठाता मौजूद रहे।

अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह जल्द कांग्रेस करेंगे ज्वाइन

हरियाणा से पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। इस बारे में दस दिन पहले कांग्रेस हाईकमान को बताया था। यह बात पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने वीरवार को गांव गंगाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वह यहां पूर्व सरपंच सिकंदर की माता दर्शना देवी की तेरहवीं पर श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने यदि उनके कहे अनुसार हरियाणा में कार्यक्रम रखा तो उनके साथ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। दिल्ली के पार्टी कार्यालय में कुछ हजार लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने की तिथि और स्थान हाईकमान ही तय करेगा। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस को हर स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। उनके बेटे के लंबे समय से मन में था कि भाजपा की विचारधारा उनके अनुरूप मेल नहीं खाती। भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग-अलग विचारधारा हैं और

कांग्रेस में वह 42 साल रहे हैं। वह सभ्य तरीके की राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तब भी कांग्रेस की बुराई नहीं की थी। अब वह भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे तो भी भाजपा की बुराई नहीं करेंगे। बृजेन्द्र के सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी जहां का भी निर्णय करेगी, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्राथमिकता हिसार की रहेगी। केजरीवाल को गिरतार कर भाजपा ने की लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरतारी पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरतार कर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत नहीं कर पाई है। इस मौके पर चौधरी छोटूराम विचार समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप चहल, जयदीप छतैहरा, नरेश बुटाना, सुरेंद्र मलिक, राजेश मलिक, जगदीश वाल्मीकि व रणबीर मौजूद रहे।

केवल राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर का दर्द समझते हैं : महबूबा मुफती

महबूबा मुफती बोली जम्मू-कश्मीर के बच्चों को सच में राहत देना चाहती है तो उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफती ने गुरुवार 28 मार्च को कहा कि कांग्रेस, सही मायने में राहुल जम्मू-कश्मीर के लोगों के दर्द और दुविधा समझते हैं। अगर चुनाव में एनडीए जीता तो यह हमारे (जम्मू-कश्मीर) लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा होगा। महबूबा ने ये बातें एक बुक भारत जोड़ो यात्रा रीक्लेमिंग इंडियाज सोल की लॉन्चिंग के दौरान कही। इस बुक में निबंधों का संग्रह है। महबूबा ने ये भी कहा कि भारत के मूल विचार को बचाने का रास्ता जम्मू और कश्मीर से होकर जाता है, जो अपने आप में एक छोटा भारत है। जम्मू-कश्मीर में कई धर्म सद्दियों से शांतिपूर्वक तरीके से साथ में रह रहे हैं। राहुल को खराब नेता बताने में भाजपा ने काफी खर्च किया— महबूबा महबूबा के मुताबिक, मैंने राहुल गांधी से कई बार बात की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका बिल्कुल अलग पक्ष देखा। मुझे कई मुद्दों पर, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, उनकी जानकारीयों पुख्ता दिखीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी को गलत तरीके से एक अज्ञानी राजनेता के रूप में पेश करने की भाजपा का कितना पैसा और ऊर्जा खर्च हुई होगी। पहले हमें देशद्रोही करार दिया जाता था— महबूबा वहीं, महबूबा ने ये भी कहा कि सिवि. लियन क्षेत्रों से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट और सुरक्षा बल हटाए जाने चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाए जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान महज

जुमला नहीं था। महबूबा ने आगे बातचीत में कहा कि अमित शाह ने यह फैसला इलेक्शन के समय लिया है, ये सिर्फ बयानबाजी बनकर तो नहीं रह जाएगी? जहां तक नागरिक इलाकों में सुरक्षा बलों या आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का सवाल है, पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोग ये मांग कर रहे हैं। पीडीपी खुद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए कई बार कह चुकी है। महबूबा मुफती का कहना है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को चुनाव से पहले हटाना कहीं जुमला तो नहीं। महबूबा बोलीं— बेकसूर लोगों को जेल से रिहा कर देना चाहिए पीडीपी प्रमुख ने जेल में बंद में जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए भी आवाज उठाई। उनका कहना है कि अगर सरकार जम्मू-कश्मीर के बच्चों को सच में राहत देना चाहती है तो उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कितने पत्रकार जेल में हैं? उन सभी लोगों को रिहा कर देना चाहिए जो बेकसूर हैं या जिन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। यदि सरकार ये कर सकेगी, तभी हमें उनकी बातों पर भरोसा होगा, नहीं तो ये सब एक जुमला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (26 मार्च) को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत भाई अफजाल बोला— स्लो पॉइजन दिया जा रहा था

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात को मौत हो गई। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:25 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था। उधर, पूरे राज्य में सुरक्षा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के भाई अफजाल ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा था। अलग-अलग मामलों में उसे 2 बार उम्रकैद हुई थी। माफिया मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने और बांदा मेडिकल कॉलेज भेजने की सूचना मिलते ही डीजीपी मुख्यालय भी हरकत में आ गया और मुख्तार और उसके समर्थकों के प्रभाव वाले पूर्वांचल के चार जिलों को तत्काल अलर्ट कर दिया गया। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी गयी। वहीं बांदा में भी सुरक्षा बढ़ाते हुए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गयी। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस को खास सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। करीब 10.30 बजे मुख्तार की हार्ट अटैक से मृत्यु होने की आधिकारिक जानकारी मिलने तक सारे बंदोबस्त कर लिए गए। हार्ट अटैक से हुई मौत करीब ढाई साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक (कार्डिया अरेस्ट) से मौत हो गई। मुख्तार को मौत से करीब तीन घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था। जहां नौ डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी थी। रात करीब साढ़े दस प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। मुख्तार का हर जेल में रुतबा रहा कैद में मर्डर के 8 केस दर्ज हुए, हाईकोर्ट ने उसको देश का

सबसे खतरनाक गिरोह कहा था पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा है। इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानउल्ला अंसारी पॉलिटिशियन थे जबकि रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुना गया। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा, उसका रुतबा हमेशा बना रहा। चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी ये बात मानते हैं। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था।

जेल में मुख्तार के रुतबे की 4 कहानियां पहली कहानी— मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब खुदवा दिया यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात को माना था। मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। दूसरी कहानी— मुख्तार बांदा जेल आया, डेढ़ साल खाली रही जेलर की कुर्सी मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए ही तैयार नहीं हुआ। बाद में दो जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और एक सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन की जॉइंट

रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सरपेंड कर दिए गए थे। तीसरी कहानी— मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के प्लेटफ़ॉर्म के कैमरे बंद हो जाते थे बांदा जेल में मुख्तार के लिए अलग से बैरक बनी थी। इसी में वह कुर्सी लगाकर बैठता था। इस दौरान वो जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था। इलस्ट्रेशनरू मंसूर नकवी बांदा जेल में मुख्तार के लिए अलग से बैरक बनी थी। इसी में वह कुर्सी लगाकर बैठता था। इस दौरान वो जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था। इलस्ट्रेशनरू मंसूर नकवी मुख्तार दो साल से बांदा जेल में बंद था। मार्च, 2023 के आखिरी हते में इस जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया था। नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। ये बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही बनी है। गेट के पास ही वह हर रोज घंटे-दो घंटे कुर्सी डालकर बैठता था। वहीं जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था।

मुख्तार जब तक वहां बैठता था, कोई उस गेट से आ-जा नहीं सकता था। मुझे जब जेल से छूटना था, तब भी मुख्तार उसी गेट पर बैठा था। इस वजह से मेरी रिहाई करीब दो घंटे लेट हुई। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, तब तक जेल के उस हिस्से के प्लेटफ़ॉर्म बंद रहते थे, ताकि वह किससे मिल रहा है, यह किसी को पता न चले। चौथी कहानी— मुख्तार की बैरक में मिले थे दशहरी आम, बाहर का खाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया था। जून, 2022 में उसकी बैरक पर छापा मारा गया। इसमें आम और होटल का खाना मिला था। जून, 2022 में बांदा जेल में डीएम ने छापा मारा था। सूत्र बताते हैं कि तब मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ-साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वह जो सुविधा चाहता, वह उसे बैरक में ही मिल जाती थी। बताया जाता है कि मुख्तार जब ट्रांसफर होकर बांदा जेल आया, तो उसके गुर्मे जेल के आसपास किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा जेल में मुख्तार की हत्या का अदेशा जताया था।

केजरीवाल पर अमेरिका-जर्मनी की टिप्पणी के बाद बोले धनखड़, न्यायपालिका पर हमें लेक्चर न दे दुनिया

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की न्यायिक प्रणाली पर टिप्पणी करने वालों की आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरतारी पर अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी के संदर्भ में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत में मजबूत न्यायिक प्रणाली है, लेकिन कुछ लोग हमें न्यायपालिका पर लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली में गुरुवार को बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले का जिक्र किए बिना उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतंत्र और तत्पर है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे न्यायिक व्यवहार पर हमें लेक्चर देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर भी कहानी

बनाने की कोशिश की जा रही है। धनखड़ ने कहा, जमीनी हकीकत से अनजान देश भारत जैसे संप्रभु देश को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह भेदभावपूर्ण है। हम उनकी अज्ञानता का खंडन करते हैं। उन्होंने कहा, सीएए भारत के पड़ोस में धार्मिक आधार पर सत्ताएं गए लोगों को राहत देने के लिए है।

कोरियन लोग लेते हैं ये सप्लीमेंट जवान और शीशे सी स्किन के लिए

फेस पर लगाएं ये देसी उबटन पार्टनर से मिलने से पहले

कोरियन कल्चर का खुमार इन दिनों लोगों पर खूब चढ़ा हुआ है। खासतौर से बात अगर यंग और हेल्दी रहने की हो, तो ज्यादातर लोग कोरियन पद्धतियों पर ही भरोसा करते हैं। ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोरियाई लोग अपनी उम्र से बहुत ज्यादा यंग और फिट दिखते हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है उनके वर्कआउट और उनकी डाइट को। ये लोग पोषक तत्वों से भरपूर मछली, सब्जियां, फर्मेंटेड फूड्स का सेवन ज्यादा करते हैं, वहीं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी इनकी फिटनेस को बढ़ावा देती है। इसके अलावा कुछ तरह की पारंपरिक चाय और रिलैक्सेशन टेक्निक भी हेल्दी लाइफस्टाइल को मंटेन करने में मदद करती हैं। अगर आप भी अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो कोरियाई लोगों की तरह कुछ सप्लीमेंट्स का उपयोग शुरू कर दीजिए। अपनी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोरियाई लोग अक्सर इसे अपने रूटीन में शामिल करते हैं। तो आइए जानते हैं इन 8 सप्लीमेंट के बारे में।

ग्रीन टी का अर्क
ग्रीन टी सदियों से कोरियाई संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी एक्सट्रेक्ट सप्लीमेंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने, हृदय स्वास्थ्य को ठीक करने और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है।

हल्दी
कोरियाई व्यंजनों में हल्दी का यूज बहुत होता है। इस जड़ी बूटी में करक्यूमिन होता है। यह अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। इसके स्वास्थ्य लाभों का जानकर कई कोरियाई लोग अब जोड़ों के स्वास्थ्य और सूजन को कम करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करने लगे हैं।

विटामिन सी
विटामिन सी इंडियन स्किन के लिए भी बहुत असरदार है। अपने

चेहरे पर नहीं आने देते

यौवन और सुंदरता को हर कोई लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। लेकिन यूवी किरणों, स्किन केयर की गलत आदतों, प्रदूषण और अन्य कारक आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र तेजी से बढ़ने का कारण बनते हैं। खासतौर से महिलाओं के चेहरे पर समय से पहले फाइन लाइन्स और रिकल्स नजर आने लगे हैं। इसके लिए हम पर्यावरण को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आपकी आहार संबंधी आदतें भी त्वचा की बनावट पर उतना ही प्रभाव डालती हैं। हम बढ़ती उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन पौष्टिक आहार के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आप भी साफ, चमकदार और जवां दिखने वाली त्वचा चाहती हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने आहार में एंटी-एजिंग खाद्य पदार्थों को भी शामिल करें। यहां ऐसे

एंटीऑक्सीडेंट गुणों और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में यह अहम भूमिका निभाता है। कोरियाई लोग अक्सर अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, जामुन और हरी सब्जियां शामिल करते हैं।

इसके अलावा कई लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स पर निर्भर हैं। खासकर टंड और लू के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये लोग इसका सेवन रोजाना करते हैं।

कोलेजन
स्किन को यंग बनाए रखने में कोलेजन की भूमिका अहम है। कोलेजन एक प्रोटीन है, जो त्वचा, बालों और नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कई कोरियाई लोग अपनी ब्यूटी डाइट में कोलेजन के सप्लीमेंट लेते हैं। माना जाता है कि ये सप्लीमेंट त्वचा की लोच और हाइड्रोजन को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं यह चेहरे पर आने वाली झुर्रियों को कम करने का अच्छा तरीका है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड
सैल्मन और मैकेरल जैसी फैट से भरपूर मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चूंकि हर कोई नियमित रूप से मछली का सेवन नहीं करता, इसलिए कई कोरियाई लोग ओमेगा-3 के सप्लीमेंट लेना पसंद करते हैं। खासकर अगर वह मछली के तेल या शैवाल से मिले, तो ज्यादा फायदेमंद होता है। यह सप्लीमेंट हृदय के स्वास्थ्य और सूजन को कम करता है, जिससे आप बढ़ती उम्र में जवां और फिट दिखाई देते हैं।

प्रोबायोटिक्स
हम भारतीय लोग पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का सेवन करते हैं। यही प्रोबायोटिक्स दक्षिण कोरिया में पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। फर्मेंटेड फूड जैसे किमची, दही और अन्य पारंपरिक कोरियाई व्यंजन गुड बैक्टीरिया के सेवन में योगदान करते हैं। हालांकि, कई

झुर्रियां, बुढ़ापे को दूर भागते हैं ये एंटी-एजिंग फूड

एंटी-एजिंग खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, जो त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आइए जानते हैं इन एंटी एजिंग फूड्स के बारे में।

अनार
अनार एजिंग के लक्षणों को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। दरअसल, इनमें एंजेलिक एसिड और प्यूनिकैलागिन यौगिक होते हैं, जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और त्वचा की लोच बनाए रखते हुए कोलेजन प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हैं।

एवोकाडो
ओमेगा-3 फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर एवोकाडो गुणों की खान है। ये आवश्यक पोषक तत्व न केवल त्वचा के स्वास्थ्य को पोषित करते हैं, बल्कि बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में भी काम करते हैं।

अंडे
अंडों को प्रोटीन का पावर हाउस

कोरियाई लोग पाचन स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का भी सेवन करने लगे हैं।

रेड जिनसेंग
रेड जिनसेंग, एक पॉपुलर पारंपरिक कोरियाई उपचार है। यह अपने एडाप्टोजेनिक गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह तनाव को दूर करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। रेड जिनसेंग का सेवन कोरियाई लोग कैप्सूल, अर्क, चाय और टॉनिक में एक कंपोनेंट के रूप में करते हैं।

कोरियाई लोगों की आदतों को कैसे अपने जीवन में लागू करें

- 1- रंगीन सब्जियों, टोफू और मछली जैसे लीन प्रोटीन और किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स के साथ संतुलित भोजन का सेवन करें।
- 2- माइंडफुल ईटिंग के लिए पोर्शन कंट्रोल पर ध्यान दें।
- 3- डेली वॉक या टाइक्वांडो जैसी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं।
- 4- सोने और जागने का शेड्यूल बनाएं।
- 5- त्वचा की देखभाल पर जोर दें।
- 6- पारंपरिक चाय पीकर हाइड्रेटेड रहें।

कोरियाई लाइफस्टाइल के लिए ये बातें भी हैं जरूरी -

- 1- संतुलित पोषण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- 2- आहार में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को शामिल करना जरूरी है।
- 3- रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करें। हर सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करें।
- 4- अच्छी मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें।
- 5- समग्र स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लें।
- 6- तनाव दूर करें।
- 7- प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और शराब का सेवन सीमित करें।
- 8- रेगुलर हेल्थ चेकअप पर ध्यान दें।
- 9- स्वस्थ जीवन के लिए सकारात्मक रिश्ते बनाना भी जरूरी है।

कहा जाता है। यह बालों, त्वचा और नाखूनों के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की आपूर्ति करते हैं। समय से पहले बुढ़ापा रोकने और मांसपेशियों की टोन बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना जरूरी है।

हरी सब्जियां
पालक, सरसों का साग और मेथी जैसी हरी सब्जियां एंटी-एजिंग गुणों के लिए मशहूर हैं।

इनमें एंटीऑक्सिडेंट, पॉलीफेनॉल और क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका सेवन करने से सेल मेंब्रेन मजबूत होती है और त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए कोलेजन को प्रोटेक्ट करती है।

ब्लूबेरी
ब्लूबेरी खाने से त्वचा पर दिखने वाले बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है।

अगर आप रोजाना ब्लूबेरी का सेवन करती रहेंगी, तो बढ़ती उम्र के निशान नजर नहीं आएंगे।

हर कोई क्लीन और एक्ने फ्री स्किन चाहता है। लेकिन व्यस्त रूटीन में त्वचा की देखभाल के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि, आजकल ऐसे बहुत से प्रोडक्ट आ गए हैं, जो आपकी ग्लोइंग स्किन की ख्वाइश को मिनटों में पूरा कर देंगे।

लेकिन बाद में इनके साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो त्वचा को लॉलेस बनाने के लिए होममेड उबटन का विकल्प बहुत अच्छा है।

यहां बताए गए तरीके से उबटन बनाकर त्वचा पर लगाएं। फिर देखिए आपका पार्टनर आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सकेगा और उसकी नजरें आपसे नहीं हटेंगी।

1. चंदन और गुलाब की पंखुड़ी वाला उबटन-
चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों वाला उबटन सदियों से स्किन केयर रूटीन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहा है। यह उबटन अपने प्रा.तिक और सुगंधित गुणों के लिए जाना जाता है। चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से बना उबटन त्वचा के लिए बहुत अच्छा काम करता है।

इससे चेहरे की गंदगी तो साफ होगी ही साथ ही डेड स्किन भी निकल जाएगी।

- सामग्री-
2 बड़े चम्मच- चंदन पाउडर
एक मुठी- सूखी गुलाब की पंखुड़ियां
1 बड़ा चम्मच- दही
कैसे बनाएं-

- सबसे पहले सूखी गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें।
- गुलाब की पंखुड़ियों के पाउडर को चंदन पाउडर के साथ मिलाएं।
- पेस्ट बनाने के लिए इसमें दही मिला सकते हैं।
- इस उबटन को अपनी त्वचा पर लगाएं और 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें।
- ठंडे पानी से धो लें।

इसके बाद सूखी टॉवल से चेहरे को थपथपाकर सुखाएं और चेहरे पर क्रीम जरूर लगाएं।

केसर और दूध का उबटन चेहरे की देखभाल के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर हमेशा भरोसे किया जाता रहा है।

केसर एक ऐसी ही नेचुरल इंग्रीडिएंट है, जो त्वचा की प्रा.तिक चमक को बढ़ाती है।

यह हमेशा से ही अपने रंग और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जानी जाती है।

जबकि दूध के पौष्टिक गुण त्वचा को मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। ऐसे में दोनों का कॉम्बिनेशन टैन को दूर करने में मदद करता है और नेचुरल ग्लो देता है।

- सामग्री
- केसर के धागे
- 2 बड़े चम्मच- दूध
1 बड़ा चम्मच - बेसन
कैसे बनाएं-

- केसर के धागों को कुछ घंटों के लिए दूध में भिगो दें।
- अब पेस्ट बनाने के लिए इसमें बेसन मिलाएं।

- इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें।

नीम और तुलसी का उबटन त्वचा की रौनक बढ़ाने के लिए नीम और तुलसी से बना उबटन बहुत अच्छा है।

चेहरे पर इसे लगाने से आपको एक चमकदार और स्वस्थ त्वचा मिलेगी।

- सामग्री
एक मुठी- नीम की पत्तियां
एक मुठी- ताजी तुलसी की पत्तियां
1 बड़ा चम्मच- मुल्लानी मिट्टी
कैसे बनाएं-

- सबसे पहले नीम और तुलसी की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें।
- अब पेस्ट में मुल्लानी मिट्टी मिलाएं।
- इस उबटन को अपनी स्किन पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट तक सूखने दें।
- अब गुनगुने पानी से धो लें और तौलिया से सुखाकर माइल्ड लोशन या क्रीम लगाएं।

चंदन और बादाम उबटन चंदन और बादाम से बना उबटन अपने प्राकृतिक और लाभकारी गुणों के लिए मशहूर है। यह उबटन न केवल त्वचा की चमक बढ़ाता है बल्कि एक कूलेंट इफेक्ट भी देता है।

- सामग्री
2 बड़े चम्मच - चंदन पाउडर
1 बड़ा चम्मच- बादाम पाउडर
एक चम्मच - शहद
दूध की कुछ बूंदें
कैसे बनाएं-

- चंदन और बादाम का उबटन बनाने के लिए एक कटोरे में चंदन और बादाम पाउडर मिलाएं।
- पेस्ट बनाने के लिए इसमें शहद और पर्याप्त मात्रा में दूध मिलाएं।
- इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें, सूखने के बाद इसे धो सकते हैं।
- यहां बताए गए आयुर्वेदिक उबटन चमकती त्वचा पाने का एक प्राकृतिक तरीका है।

इस वैलेंटाइन डे से पहले इन घरेलू उबटन को अपने स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपनी त्वचा की चमक और बनावट में अंतर देखें।

वैसे तो ये सभी उबटन प्राकृतिक चीजों से बने हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

त्वचा की रौनक बढ़ाने के लिए चेहरे पर इसे लगाने से आपको एक चमकदार और स्वस्थ त्वचा मिलेगी। फिर भी इस्तेमाल से पहले त्वचा पर पैच टेस्ट करके जरूर देख लें।

नोट- आपका सामना की हेल्थ, युवा, शिक्षा सामना कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से पेशेवर पत्रकारों द्वारा बातचीत के आधार पर पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किये जाते हैं। आपका सामना लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी, शिक्षा, जॉब के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर, शिक्षक से परामर्श लें।

जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है।

-डॉ० श्रीमशव अंबेडकर

संपादकीय

चुनावी बॉन्ड योजना बंधुआ एहसान

चुनावी बॉन्ड के खरीददारों और प्राप्तकर्ताओं से जुड़े विवरणों के सामने आने के बाद से होने वाले घिनौने खुलासे संशयवादियों की इस शुरुआती आशंका की पुष्टि करते हैं कि गुमनाम राजनीतिक चंदे की इस योजना के अवांछित नतीजे होंगे। संभावित लाभ से जुड़ी सौदेबाजियों से लेकर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विभिन्न कंपनियों की जांच और फिर इन कंपनियों द्वारा की गई सैकड़ों करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड की खरीद के बीच के प्रत्यक्ष रिश्ते तक, इस योजना के तहत ठीक वही सब हुआ जैसा कि इसके विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी। चुनावी बॉन्ड खरीदने और उन्हें राजनीतिक दलों को दान करने के लिए मुखौटा कंपनियों एवं घाटे में चल रही संस्थाओं का इस्तेमाल किए जाने की आशंका सच होती दिख रही है। नियमों में कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे के एक निश्चित प्रतिशत तक ही राजनीतिक चंदा दे सकने संबंधी छूट से इस योजना के अवैध बन जाने का तर्क सही साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन चिंताओं को जाहिर करके, गलत कार्यों की संभावना को चिन्हित करके और इस बॉन्ड योजना को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देकर अच्छा काम किया। हालांकि, कई सालों तक इस योजना के संचालन पर रोक लगाए बिना इसकी विभिन्न चुनौतियों से निपटने में हुई देरी के अपने खामियाजे हुए हैं। लोकतंत्र की बेहतरी चाहने वाले सभी लोगों के लिए यह एक गंभीर बात है कि राजनीतिक और कॉरपोरेट वर्ग ने जनता की इस आशंका को सच साबित किया है कि वे चुनाव अभियान को दूषित करने वाले नापाक धन की समस्या को हल करने के बजाय एक-दूसरे को फायदा पहुंचाने की खातिर इस योजना का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।

किस दल को किसने चंदा दिया है, इसके बारे में कुछ विवरण अब सामने आ रहे हैं। इसका श्रेय उन दलों को जाता है, जिन्होंने चंदा देने वालों के नामों का खुलासा किया है और अदालत के आदेश पर उस जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। हालांकि यह बेहद निराशाजनक है कि सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने ही सीलबंद लिफाफे में भी इसका खुलासा नहीं किया। संभव है कि हर बॉन्ड में अंकित विशिष्ट नंबरों से जुड़ी जानकारी के सामने आने के बाद आने वाले दिनों में और भी खुलासा हों। जांच एजेंसियों की भूमिका, खासकर वर्तमान शासन के तहत, राजनीतिक रूप से विवादास्पद रही है। लेकिन एक तरफ छापेमारियां एवं गिरफ्तारियां और दूसरी तरफ बॉन्ड की खरीद की तारीखों के बीच के मजबूत रिश्ते ने केंद्र सरकार की छवि को धूमिल किया है। यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन होगा जब इस किस्मकी जानकारी सामने आयेगी कि एजेंसियों का इस्तेमाल लोगों को राजनीतिक चंदा देने के लिए मजबूर करने के मकसद से किया गया था। इसमें कोई अचरज नहीं कि भाजपा इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर सामने आई है। उसे 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली है और उसने बॉन्ड के रास्ते दिए गए कुल चंदे का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया है। हालांकि, इस चंदे को अपने लोकसभा सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या के मद्देनजर तुलनात्मक रूप से कम बताने का उसका प्रयास थोथी दलील या इससे भी ज्यादा खराब तरीके से कहें तो, खुद को दोषी करार देने वाला है। सत्ता और प्रभाव के चलते राजनीतिक चंदे हासिल होते हैं, लेकिन बेशर्मी भरे प्रदर्शन या इनाम के वादे के जरिए किया गया उनका दुरुपयोग अंत में लोकतंत्र के लिए ही घातक साबित होगा।

लोकसभा के आम चुनाव मतदान की कसौटी पर

आगामी 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव सात चरणों और 44 दिनों में होंगे। मतों की गिनती 4 जून को होगी। यह एलान चुनावी प्रक्रिया की एक औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन चुनाव प्रचार भारतीय राजनीति का एक ऐसा शाश्वत मामला बन गया है, मानो सत्तारूढ़ भाजपा के एक राष्ट्र, एक चुनाव के आह्वान को सही ठहराना हो। भाजपा का तर्क है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव से चुनाव प्रचार में लगने वाला समय कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव और अन्य विवादास्पद सवाल लंबे समय तक चलने वाले चुनावी मौसम, जो दुनिया में कहीं भी इस किस्म की सबसे बड़ी कवायद है, का परिपेक्ष्य तैयार करते हैं। भारत के पास जहां अपने जीवंत लोकतंत्र और स्फूर्तिदायक विविधता पर गर्व करने की पर्याप्त वजहें हैं, वहीं इस दिशा में किया गया एक ईमानदार आत्मनिरीक्षण बुद्धिमानी भरा साबित हो सकता है। वर्ष 2019 से, भारत में तेजी से और बड़े पैमाने पर कई अच्छे एवं बुरे बदलाव हुए हैं। स्वाभाविक रूप से, भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल को प्रगति और समृद्धि के युग के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। उसका यह प्रचार जहां जोर-शोर से चल रहा है, वहीं विपक्ष की ओर से इसकी आलोचना करने की कोशिशें कमजोर रही हैं। यह बेमेल प्रतिस्पर्धा काफी हद तक दूसरे दलों और राजनीतिक प्रक्रिया में संलग्न मीडिया, नौकरशाही एवं निजी क्षेत्र जैसे तत्वों को प्रभावित करने के लिए भाजपा द्वारा की गई राज्य की शक्ति के दुरुपयोग का नतीजा है। अंतर्निहित समस्याएं विपक्ष को और कमजोर करती हैं। तथ्य यह है कि प्रमुख विपक्षी दल के बैंक खाते को एक कथित प्रक्रियात्मक चूक, जोकि साबित होने पर भी एक छोटी सी चूक ही है, के आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है। यह हरकत काफी कुछ बताती है कि राज्य की एजेंसियां किस कदर पलड़े को एक तरफ झुका रही हैं।

चुनावी बॉन्ड योजना, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, से जुड़े अब तक हुए तमाम खुलासे भी चुनाव प्रक्रिया में घटती निष्पक्षता के एक बेहद चिंताजनक रूझान को दर्शाते हैं। हालात के मद्देनजर, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के लिए चुनाव प्रक्रिया को न सिर्फ निष्पक्ष बनाये रखना बल्कि उसे ऐसा दिखाना भी सुनिश्चित करना एक मुश्किल भरा काम होगा। ईसीआई के एक सदस्य के अचानक पद छोड़ देने और जल्दबाजी में की गई दो नए सदस्यों की नियुक्ति से यह चुनौती और भी जटिल हो गई है।

रूसी चुनाव में पुतिन की जीत खोखली जीत

रूस में 15-17 मार्च को हुए चुनाव का नतीजा पहला वोट पडने के पहले ही हर किसी को पता था। सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि लगभग एक चौथाई सदी से देश का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत का अंतर क्या रहेगा। सोमवार को, रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) ने कहा कि पुतिन ने लगभग 88 फीसदी मत हासिल किये हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाई खारिता, नोव को 4.31 फीसदी मत मिले। सीईसी प्रमुख एला पैम्फिलोवा के मुताबिक, देश में 77.44 फीसदी का रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला और नतीजों ने यह दिखाया कि रूस लंबे समय से देश की अगुवाई कर रहे नेता के तहत एकजुट है। तमाम व्यावहारिक अर्थों में, यह बड़े एहतिघात से प्रबंधित चुनाव था जिसका सिर्फ एक संभावित नतीजा आना था। सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को चुनाव में खड़े होने की इजाजत दी गयी, जिन्हें क्रेमलिन सहन करने को तैयार था। जो पुतिन की नीतियों के आलोचक थे, उन्हें तकनीकी आधार पर रोक दिया गया। रूसी राज्य ने चुनाव से पहले,

यूक्रेन युद्ध की किसी आलोचना को अपराध बनाने वाला एक कानून भी पारित किया था। इस युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहे पुतिन के लिए, यह चुनाव दुनिया को यह बताने का मौका था कि देश उनके पीछे एकजुट है। गुजरते वक्त के साथ, 71 वर्षीय पुतिन ने नियमित चुनाव और थोड़ी असहमति की इजाजत के साथ एक मजबूत पकड़ वाले राज्य के जटिल मॉडल में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। कम-से-कम इस बात के लिए उनकी तारीफ बनती है कि वह एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। बहुत से रूसियों की नजर में, सोवियत संघ के पतन से शुरू हुए 1990 के अपमान के दशक के बाद, उन्होंने 2000 के दशक के शुरुआती सालों में राज्य का पुनर्निर्माण किया। ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के पारंपरिक मूल्यों में समाये राज्यवाद ने सोवियत दौर के राज्य-स्वीकृत साम्यवाद (कम्युनिज्म) की जगह ले ली। रूस की महान शक्ति का गौरव लौटाने की कोशिश में, वह पश्चिम के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने रूसी सरजमीन पर चल रही जंगों का खात्मा किया, आर्थिक एवं

राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की और 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के साथ देश की सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन उन्होंने राज्य को एक ऐसे सैन्यवादी, सत्तावादी तंत्र में भी बदल दिया जो घरेलू मोर्चे पर पूरा दबदबा और विदेश में पश्चिम के खिलाफ प्रति-संतुलन चाहता था। उनके सबसे मुखर राजनीतिक विरोधियों में से दो, बोरिस नेमत्सोव और एलेक्सी नवेलनी, दुनिया से जा चुके हैं, जबकि कई अन्य जेल में हैं। मीडिया के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। और राज्य की संस्थाएं व्यावहारिक तौर पर क्रेमलिन की शाखाएं बन गयी हैं। अपनी एकतरफा जीत के साथ, पुतिन शायद आगे भी ताकत दिखायेंगे और यथास्थिति बनाये रखेंगे। लेकिन यह चुनाव (जिसका लक्ष्य पुतिन का संख्याबल मजबूत करना था) कराने के उनके शासन के सूक्ष्म-प्रबंधित तरीके, और छोटी से छोटी असहमति को भी कुचलने की उसकी अतिरिक्त-उत्साही कोशिश ने पुतिन द्वारा निर्मित शासन-व्यवस्था की दबंग छवि को पुष्ट करने के बजाय उसमें निहित कमजोरियों को ही उजागर किया है।

निर्यात वैश्विक और व्यापार की पहली

उत्तर-चढ़ाव भरे व्यापारिक वर्ष के अंत में, फरवरी महीने के दौरान भारत का माल निर्यात 11.9 फीसदी बढ़ गया, जोकि पिछले 20 महीनों में हुई सबसे अच्छी वृद्धि है। कुल 41.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा बीते 11 महीनों में सबसे ज्यादा है और पिछले दो सालों में यह सिर्फ तीसरी मर्तबा है जब भारतीय निर्यात ने 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार किया है। उल्लेखनीय है कि यह उछाल इस साल के पहले दस महीनों में 35.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के औसत निर्यात से काफी ज्यादा है और लाल सागर एवं सूखा प्रभावित पनामा नहर में व्याप्त व्यवधानों से जुड़ी चिंताओं के बीच आया है। लाल सागर और पनामा नहर के व्यवधानों ने इन महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है और इसके चलते खेपों को ले जाने में लगाने वाले समय और लागत में बढ़ोतरी हो गई है। अब जबकि पिछले दो महीनों के व्यापार के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत को अभी भी यूरोप और अमेरिका के प्रमुख बाजारों में पहुंचने में आने वाली रसद (लॉजिस्टिक्स) संबंधी चुनौतियों का पूरा असर महसूस नहीं हुआ है, लिहाजा इस किस्म का निष्कर्ष कुछ ज्यादा ही सरल साबित हो सकता है। यह सुखद है कि फरवरी के कुछ आंकड़े उन खेपों को

दर्शाते हैं जो शायद पहले भेजे गए थे और लंबे मार्गों का इस्तेमाल करके पिछले महीने ही अपने गंतव्य पर पहुंचे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लंबित ऑर्डरों के पूरा होने और मांग में सुधार का संयुक्त असर हुआ है। हालांकि, ब्याज दरों के अभी भी ऊंची रहने के चलते वैश्विक मांग में वह उछाल नहीं दिख पाया है जिसकी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने 2024 में होने की उम्मीद की थी। डब्ल्यूटीओ को उम्मीद है कि 2023 में 0.8 फीसदी की गिरावट के बाद इस साल वैश्विक व्यापार में 3.3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसके अपने हिसाब से, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर नाम के पैमाने के आधार पर, चीजें अभी भी बेहतर नहीं हुई हैं। बीते 8 मार्च तक उक्त बैरोमीटर की रीडिंग महज 100.6 थी। इस बैरोमीटर पर 100 से ज्यादा की रीडिंग ऊपर की ओर रूझान वाले आयात-निर्यात (एक्जिज्म) की मात्रा को दर्शाती है। निर्यात के ऑर्डर का पैरामीटर जहां बस थोड़ा सा ही ऊपर चढ़कर 101.7 पर रहा, वहीं कंटेनर का लदान लुढ़कर 98.6 पर आ गया। डब्ल्यूटीओ ने चेतावनी दी है कि 2023 के कमजोर आधार प्रभावों की वजह से 2024 की पहली तिमाही में कुछ मामूली बढ़त दिख सकती है, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों और भू-राजनैतिक तनावों की

वजह से ऐसी कोई भी बढ़त आसानी से बेपटरी हो सकती है। नीति-निर्माता पिछले साल के समग्र निर्यात (माल और सेवाओं को मिलाकर) के रिकॉर्ड को पार करने को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें माल दुलाई के भाड़े में होने वाली बढ़ोतरी के प्रभाव सहित मौजूदा जोखिमों और चुनौतियों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। जहां 2023-24 के निर्यात की कमजोर कहानी (अब तक -3.5 फीसदी) से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात बाहर बना रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक घटकों के व्यापार से संबंधित डब्ल्यूटीओ की ताजा बैरोमीटर रीडिंग गिरकर 95.6 पर आ गई है। इसकी झलक फरवरी के आंकड़ों में दिखाई देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आयात और निर्यात, दोनों में आंशिक रूप से एक फीसदी से थोड़ा ज्यादा की वृद्धि हुई है। फिलहाल, महंगे सोने की आवक की वजह से पिछले महीने आयात के 17 महीने की उच्च गति पर पहुंच जाने के बावजूद व्यापार घाटा चिंता का सबब नहीं होना चाहिए। निर्यातकों, खासतौर पर बुरी तरह से प्रभावित कपड़ा और रत्न एवं आभूषण जैसे रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों से जुड़े व्यापारियों, को समर्थन प्रदान करने के लिए बेहतर तरीके ढूंढना महत्वपूर्ण बना हुआ है।

राहुल गांधी और उनकी यात्रा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, का समापन 17 मार्च को मुंबई में एक रैली के साथ हुआ, जिसमें पार्टी के कुछ सहयोगियों की भागीदारी भी देखी गयी। इस यात्रा के दो संस्करणों के दौरान, गांधी ने देश के चप्पे-चप्पे से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नाप डाली और समाज के तमाम तबकों से आने वाले बहुत से लोगों से मुलाकात की। इस प्रक्रिया में उन्होंने, भारत में भाजपा-विरोधी राजनीति के सबसे मुखर चेहरे के रूप में उभरने के लिए एक नेता के बतौर अपने विकास में भी कुछ दूरी तय की है। अगर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक के पहले

संस्करण में नवीनता और हर्षातिरेक था, तो मणिपुर से मुंबई तक का दूसरा संस्करण ज्यादा सादा और व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित था। मनोरम ग्रामीण क्षेत्रों से राहुल गांधी के पैदल सफर के साथ पहली यात्रा ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानच नारे के इर्द-गिर्द गढ़ा गया प्यार और सामंजस्य का एक अमूर्त संदेश लोगों तक पहुंचाया। तात्कालिक राजनीति की उम्मीदों से गांधी को बेअसर रखने के लिए, कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह यात्रा एक चुनावी कवायद नहीं, बल्कि एक विचारधारात्मक अभियान है। इस यात्रा ने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ चुनावी फायदा दिलाया जहां

यात्रा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में वह हार गयी। दूसरे संस्करण में, यात्रा का थीम उस सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द रखा गया था जो सत्ता में जातीय समूहों की व्यापक नुमाइंदगी का एक बेहतर नाम है। दोनों यात्राओं ने पार्टी कैडरों में जोश भरने का लक्ष्य हासिल किया है। आम चुनाव से पहले कैडरों ने खुद को उपयुक्त ढंग से काम में लगाया और पार्टी नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ पाया। केंद्र में भाजपा-विरोधी गठबंधन को एकजुट रखने के लिए लडखड़ाती, कमजोर और लचीली कांग्रेस एक ज्यादा तगड़ा गोंद है।

सीजेआई को वकीलों का पत्र वकीलों ने कहा न्यायपालिका खतरे में

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संकृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात कही थी।

पीएम मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।

दरअसल, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सावले समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यवसायिक दबाव से बचाना होगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर चिट्ठी वाले एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए ये बातें लिखीं। खडगे का जवाब— आप संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर

नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने जवाब दिया। खडगे ने सोशल मीडिया पर लिखा— आप (मोदी) न्यायपालिका की बात कर रहे हैं।

आप ये कैसे भूल गए कि आपके ही शासन काल में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस को प्रेस कांफ्रेंस करनी पड़ी थी। उन्होंने लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ चेताया था। बाद में उनमें से एक जस्टिस को आपकी सरकार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया।

खडगे ने आगे लिखा— आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में एक पूर्व हाई कोर्ट जस्टिस को मैदान में उतारा है। उन्हें यह उम्मीदवारी क्यों दी गई? आप ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

मोदी जी, आपकी तरफ से एक के बाद एक संस्थानों को झुकाने की को.

शिश की जाती रही है, इसलिए अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना बंद करें। आप लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने और संविधान को चोट पहुंचाने की कला में माहिर हैं।

26 मार्च को लिखी गई चिठी में क्या है

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीजेआई चंद्रचूड़ को चिठी लिखने वाले 600 से ज्यादा वकीलों में हरीश सावले के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, अदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला और स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैं।

वकीलों ने लिखा, रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की को. शिश कर रहा है। यह गुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे-पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द्र और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात हैं, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा हैं।

ये विशेष समूह कई तरीके से काम करता है। ये हमारी अदालतों के स्वर्णिम अतीत का हवाला देते हैं और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। ये महज जानबूझकर दिए गए बयान हैं ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। यह देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं, ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। यह हरकत ना केवल हमारी अदालतों का असम्मान है, बल्कि मानहानि भी है। यह हमारी अदालत।

की गरिमा पर किया गया हमला है। माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं। उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही हैं। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं, जहां कानून नाम की चीज नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है।

2 पॉइंट्स का विशेष जिक्र

1. राजनेताओं का दोहरा चरित्र ये देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता है तो वे कोर्ट के भीतर ही कोर्ट की आला.

चना करते हैं और फिर बाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं। आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है, उसके लिए ये दोहरा चरित्र खतरा है। 2. पीठ पीछे हमला, झूठी जानकारियां कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं।

ऐसा वे अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी उसूलों पर हमला है। इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब ये ऐसा कर रहे हैं। हमने यह चीज 2018-19 में भी देखी थी। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार, कहा— चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने दो नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में ज्यूडीशियल मेंबर होना चाहिए।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे व्यवस्था फेल जाएगी।

बीते 10 वर्षों में 38400 प्रवासियों की डूबने की वजह से गई जान, यूएन रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के में बताया गया है कि बीते 10 वर्षों में 64,000 प्रवासियों की मृत्यु हुई है। इनमें से करीब 38,400 प्रवासियों की मौत समुद्र में डूबने से हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भूमध्य सागर में सबसे ज्यादा 27,000 प्रवासियों की मौतें हुई हैं।

खतरनाक भूमध्य सागर में मारे गए 27,000 प्रवासी भूमध्य सागर के रास्ते कई प्रवासी उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। आईओएम के

डेटा विश्लेषक एंड्रिया गार्सिया बोरजा ने बताया कि भूमध्य सागर खतरनाक क्षेत्र है और यहां यात्राएं करना बेहद जोखिम भरा साबित होता है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य सागर के आंकड़ों को काफी गहनता से देखा गया है। उनके मुता. बिक सहारा रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों की निगरानी करना कठिन था क्योंकि वहां का विश्वसनीय डेटा आना मुश्किल था।

वर्ष 2023 में प्रवासन मार्गों पर 8,500 लोगों की मौत आधे से अधिक मामलों में, आईओएम प्रवासी का लिंग या उम्र जानने में

असमर्थ रहा। जिन जगहों में प्रवासी की पहचान की जा सकती है, वहां एक—तिहाई से अधिक प्रवासी संघर्ष वाले देशों या बड़ी शरणार्थी आबादी वाले देशों से आए थे। यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 में दुनिया भर के प्रवासन मार्गों पर 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आईओएम का कहना है कि इस लिहाज से साल 2023 सबसे खतरनाक साल कहा जा सकता है। साल 2024 के आंकड़े भी चिंताजनक हो सकते हैं।

आईओएम के अनुसार इन रास्तों पर मजबूत बचाव क्षमताएं और सुरक्षित प्रवासन मार्ग की बेहद आवश्यकता है।

महिलाओं को सरेआम कोड़े भी मारे जाएंगे तालिबान अवैध संबंध पर पत्थर मारकर सजा देगा

2021 में सत्ता में वापसी के बाद से तालिबान हुकूमत ने महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक, जो भी महिला अडल्ट्री (पति के अलावा दूसरे पुरुष से संबंध बनाना) मामले में दोषी हुई, उसकी पत्थरों से मार-मारकर हत्या कर दी जाएगी।

एक ऑडियो मैसेज में अखुंदजादा ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को चुनौती देते हुए इस्लामिक कानून शरिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा— आप कहते हैं कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है जब हम उन्हें पत्थर मारकर मार देते हैं, लेकिन जल्द ही एडल्ट्री के लिए यह सजा लागू की जाएगी। दोषी महिलाओं को सरेआम कोड़े और पत्थर मारे जाएंगे।

तालिबानी लीडर ने कहा— महिलाओं के अधिकार शरिया के खिलाफ

अखुंदजादा ने कहा— क्या महिलाएं वो अधिकार चाहती हैं जिनकी बात पश्चिमी देश कर रहे हैं? ऐसे सभी अधिकार शरिया और मौलवियों की राय के खिलाफ हैं। वही मौलवी जिन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को उखाड़ फेंका। हमने पश्चिमी लोगों के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी और जरूरत पड़ी तो हम अगले 20 सालों तक भी लड़ाई लड़ते रहेंगे।

तालिबानी नेता ने आगे कहा— जब हमने काबुल पर दोबारा कब्जा किया था तब हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। हम चुपचाप बैठकर चाय नहीं पिएंगे। हम अफगानिस्तान में शरिया वापस लाकर रहेंगे।

तालिबान ने खत्म किए महिलाओं के अधिकार

अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने आश्वासन दिया था कि वो महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करेगा। उसके बावजूद वहां

लगातार इनके अधिकारों को कम किया जा रहा है। पहले लड़कियों की मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रोक लगी।

ज्यादातर रोजगारों से महिलाओं को निकाल दिया गया या फिर उनके परिवार के ही किसी पुरुष को उनकी जगह रख लिया गया। अफगानिस्तान में महिलाओं के ब्यूटी पार्लर जाने और स्पोर्ट्स खेलने जैसे कई कामों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अफगानिस्तान में लड़कियों को यूनिवर्सिटी में घुसने से रोक दिया था अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान ने पिछले साल कई लड़कियों को बाल्ख इलाके में यूनिवर्सिटी में घुसने से इसलिए रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने ठीक से अपना मुंह नहीं ढका हुआ था। इस बीच यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा था कि अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसकी इंटरनेशनल कानूनों के तहत जांच की जानी चाहिए।

क्या है अफगानिस्तान का शरिया कानून

तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कहा था कि देश में शरिया कानून लागू होगा। दरअसल, शरिया इस्लाम को मानने वाले लोग। के लिए एक लीगल सिस्टम की तरह है। कई इस्लामी देशों में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि, पाकिस्तान समेत ज्यादातर इस्लामी देशों में यह पूरी तरह लागू नहीं है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कई तरह के बड़े मसलों पर कानून हैं।

शरिया में पारिवारिक, वित्त और व्यवसाय से जुड़े कानून शामिल हैं। शराब पीना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या तस्करी, शरिया कानून के तहत बड़े अपराधों में से एक है। यही वजह है कि इन अपराधों में कड़ी सजा के नियम हैं।

चीन ने नेपाल से की परियोजना में तेजी लाने की अपील, मंत्री नारायण श्रेष्ठ का बीजिंग दौरा

नेपाल की नई सरकार से चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव(बीआरआई) परियोजनाआ.

के लिए कार्यान्वयन योजना को अंतिम रूप देने की अपील की है। गौरतलब है कि इस परियोजना के चलते नेपाल की राजनीतिक में कई परिवर्तनों का दौरा देखा है। पद संभालने के बाद अपनी पहली चीन यात्रा पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की मंगलवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुआ बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई।

बीआरआई के लिए बेताब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव(बीआरआई) परियोजना चीन की एक महत्वकांक्षी योजना है। जिसको गति देने के लिए लगातार चीन काम कर रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड द्वारा नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी—लेनिनवादी) के साथ सरकार बनाने के बाद नेपाल में नया राजनीतिक गठबंधन देखने को

मिल रहा है। इसका नेतृत्व चीन समर्थक नेता केपी शर्मा ओली कर रहे हैं।

नेपाल रणनीतिक साझेदार के रूप में अहम— वांग यी

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि एक मित्र पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन ने हमेशा नेपाल को अपनी पड़ोस कूटनीति की एक महत्वपूर्ण दिशा में रखा है। वांग ने श्रेष्ठ से कहा कि चीन उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट और रोड सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ काम करने के लिए तैयार है

वांग यी कहा कि चीन अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में नेपाल का दृढ़ता से समर्थन करता है और नेपाल के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सहायता करना जारी रखेगा। इस बीच, नेपाल ने बैठक के दौरान दोनों देशों ने बीआरआई के कार्यान्वयन योजना पर बहुत जल्द हस्ताक्षर करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।